गहलोत सरकार ने भी अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने के मामले में सख्ती दिखाते हुये रीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा की गोपालपुरा बाइपास के पास 1667 वर्गगज में बनी अवैध इमारत को ध्वस्त करवा दिया है। जे.डी.ए. के अवैध निर्माण निरोधक दस्ते ने मंगलवार को इस चार मंजिला इमारत को तोड़ने की कार्रवाई की। रामकृपाल मीणा ने यहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कॉलेज और स्कूल बना रखी थी।

वायु सेना में महिला पायलटों को एक्सिपेरिमैंटल नहीं परमानैंट कमीशन मिलेगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस निर्णय की घोषणा की

नई दिल्ली, 1 फरवरी (वार्ता)। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए वायु सेना में अब महिलाओं को प्रायोगिक के बजाय स्थायी योजना के तहत लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को खुद इस निर्णय की घोषणा की। सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने वायु सेना में महिला लड़ाकू पायलटों को भर्ती करने की प्रायोगिक योजना को स्थाई योजना में बदलने का निर्णय लिया है। यह भारत की नारी शक्ति की क्षमता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारी सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्धता का प्रमाण है।

वायु सेना में महिला पायलटों को लड़ाकू भूमिका के लिए पहली बार वर्ष 2016 में मौका दिया गया था जिसके बाद 3 महिला अधिकारियों ने लड़ाकू विमान के पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया था। वर्ष 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने अकेले लड़ाकू विमान उड़ा कर इतिहास रचा था।

उल्लेखनीय है कि, उच्चतम न्यायालय ने कुछ महीने पहले ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं की भर्ती को मंजूरी देते हुए सरकार से अकादमी के दरवाजे महिलाओं के लिए खोलने का आदेश दिया था।

सरकार द्वारा प्रायोगिक आधार पर महिलाओं के लिए फाइटर स्ट्रीम खोलने का फैसला करने के एक साल से भी कम समय बाद, चतुर्वेदी जुलाई 2016 में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन की गई तीन सदस्यीय महिला टीम का हिस्सा थीं। 2020 में, नौसेना ने डोर्नियर समुद्री विमान पर महिला पायलटों के अपने पहले बैच को तैनात करने की घोषणा की। इसने विमानवाहक पोत आई.एन.एस. विक्रमादित्य सहित लगभग 15 अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर 28 महिला अधिकारियों को तैनात किया है और इस तरह की और नियुक्तियों की योजना के साथ संख्या बढ़ने की तैयारी है।

2019 में सेना ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिलाओं को सैन्य पुलिस में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की। सैन्य पुलिस की भूमिका में छावनियों और सेना प्रतिष्ठानों की पुलिसिंग, सैनिकों द्वारा नियमों और विनियमों के उल्लंघन को रोकना, शांति और युद्ध के दौरान सैनिकों की आवाजाही के साथ-साथ रसद को बनाए रखना और जब भी आवश्यक हो, नागरिक पुलिस को सहायता प्रदान करना शामिल है। 2016 में आई.ए.एफ. की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने की एक्सपेरिमेंट योजना लागू होने के बाद 16 महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया है। ये वायु सेना के इतिहास में एक बड़ा क्षण था।

वायुसेना के एक प्रवक्ता ने कहा, रक्षा मंत्रालय ने इसे स्थायी योजना बनाने की मंजूरी दे दी है।" यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए नए दरवाजे खोले गए हैं। नौसेना अपने पुरुष समकक्षों के साथ युद्धपोतों पर सवार होने के लिए उन्हें और अधिक अवसर देने की योजना के साथ आगे बढ़ रही है, सेना ने उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति दी है और वे स्थायी कमीशन की पात्र हैं।

वित्त मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देने वाली योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया। इसी प्रकार, ईस्टर्न एंड वैस्टर्न डैडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स (डी.एफ.सी.) को पूरा करने, या रेल की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। सन् 2019 से अब तक यह तीसरा वर्ष है, जब ट्रान्सपोर्टरों का ऑपरेटिंग रेशियो (एक रुपया कमाने के लिये खर्च किये गये पैसे) 100 प्रतिशत से ऊपर चला गया है, जबकि पेंशन व्यय की व्यवस्था सरकारी तथा एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट से करके इण्डियन रेलवे (आई.आर.) इसे 100 प्रतिशत से नीचे रखने की कला प्रदर्शित कर चुका है।

रेल -कन्सल्टैंट सुधांशुमणि ने कहा, "पिछले दो वर्षों में, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सी एंड ए जी) ने आई.आर. को आँकड़ों में गड़बड़ करने के लिये झाड़ लगाई है।" आई.आर. को आज कर्ज के ब्याज को चुकाने में स्थगन मिल गया, लेकिन इसका बकाया कर्ज आज की स्थिति में 4 लाख करोड़ से ज्यादा है। जब इस स्थगन-काल की समाप्ति शुरु होगी, कर्ज की राशि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। मणि ने कहा, "इस बजट में पूँजीगत व्यय पर 2.45 लाख करोड़ रु. और आवंटित किये गये हैं, जबकि समझदारी यह होती कि इस खर्च में कटौती की जाती तथा निवेश की वापसी के पूर्व और बाद के ऑडिट का और अधिक ताकतवर तंत्र स्थापित किया जाता। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य राजेश अग्रवाल ने कहा कि, इस समय जरुरत इस बात की थी कि कोई न्यायिक कमेटी गठित की जाती तथा रेल-वित्त पर श्वेत पत्र जारी किया जाता।

रीट पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल मीणा का स्कूल-कॉलेज ध्वस्त

गहलोत सरकार ने भी अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने के मामले में सख्ती दिखाई

जयपुर, 1 फरवरी (कासं)। रीट पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल मीणा ने गोपालपुरा बायपास के नजदीक जगन्नाथपुरी में सरकारी जमीन पर कब्जा करके एस.एस.कॉलेज और स्कूल बना रखी थी, इस बिल्डिंग पर मंगलवार को जेडीए ने बुलडोजर चलाया।

प्रवर्तन टीम ने करीब 1667 वर्गगज पर बनीं इस चार मंजिला इमारत को ध्वस्त किया। यहां पर 9 कमरे बनाये हुए थे, इसी इमारत की चौथी मंजिल पर आरोपी रामकृपाल और उसके परिजन रहते थे। इस कार्रवाई के बाद चर्चा है कि जिस तरह से उत्तरप्रदेश (यूपी) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपरलीक करने वाले आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाये हैं, ठीक वैसे ही राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती दिखाने का दिखावा किया है।

- **जयपुर में गोपालपुरा बाईपास स्थित जगन्नाथपुरी में 1667 वर्ग गज सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी चार मंजिला अवैध इमारत।**

जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि, गोपालपुरा बायपास के नजदीक जगन्नाथपुरी में जहां पर यह कॉलेज और स्कूल बना हुआ था, उसका बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर था। जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तभी जोन उपायुक्त को कहकर मौके की रिपोर्ट मंगवाई। स्कूल-कॉलेज सरकारी जमीन पर बने होने की पुष्टि होते ही इस बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश दे दिये। मंगलवार से मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशन में बिल्डिंग को तोड़कर जमीन पर कब्जा करने का काम शुरू हो चुका है। इस जमीन पर जेडीए संपत्ति का बोर्ड लगाया जायेगा।

"मोबाइल व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वक्तव्य देने के लिए भी उन्होंने कागज़ का सहारा लिया।

जी.एस.टी. की उच्चतम प्राप्तिओं के बारे में घोषणा करते समय भी उनके हाथ में एक कागज़ था। इसे वो अपने बजट भाषण में शामिल नहीं कर पाई थीं।

प्रधानमंत्री ने पूरा बजट भाषण सुना तथा जब भी वित्त मंत्री ने कोई महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने अन्य सदस्यों के साथ मेज थपथपाकर उसका स्वागत किया।

सिद्धू अब केवल अमृतसर से ही चुनाव लड़ेंगे

अमृतसर, 1 फरवरी (वार्ता)। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती आज स्वीकार की।

- **सिद्धू ने मजीठिया की चुनौती हाथोंहाथ स्वीकार की।**
- **मजीठिया ने सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ने तथा अमृतसर विधानसभा सीट से सिद्धू को उनके सामने खड़े होने की चुनौती दी थी।**

मजीठिया ने यहां मीडिया को सम्बोधित करते हुये कहा कि वह अब दो जगह से नहीं बल्कि अमृतसर पूर्व से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी गनीव कौर उनके स्थान पर मजीठा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। कौर ने गत सोमवार को मजीठा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था।

कांग्रेस ने अखिलेश व शिवपाल यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे

कांग्रेस का मकसद है कि, वह भाजपा को हराने में अखिलेश की पूर्ण मदद करना चाहती है

लखनऊ, 1 फरवरी। मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और इटावा की जसवंतनगर सीट से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया व सपा-प्रसपा गठबंधन के उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से परहेज किया है। ऐसा करके कांग्रेस ने भविष्य में भाजपा के खिलाफ जरूरत पड़ने पर समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने का स्पष्ट संकेत दिया है। हालांकि, कांग्रेस ने करहल सीट पर पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन मंगलवार को नामांकन करने से रोक दिया।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। यह बात और है कि कांग्रेस ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ अब प्रत्याशी नहीं उतारने का

- **ऐसा करके कांग्रेस ने भविष्य में भाजपा के खिलाफ जरूरत पड़ने पर समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने का स्पष्ट संकेत दिया है।**

निर्णय किया है। चुनाव की आहट तेज होते ही कांग्रेस और सपा के गठबंधन की अटकलों को अखिलेश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि बड़े दलों का स्ट्राइक रेट खराब होता है। उनका इशारा कांग्रेस के साथ 2017 में हुए सपा के गठबंधन की ओर था। सपा और कांग्रेस दोनों का मुख्य लक्ष्य भाजपा को हराना है।

बीते दिनों एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि विधान सभा चुनाव के बाद यदि सपा को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की जरूरत पड़ी तो इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस के इस कदम को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है।

हालांकि, इस बारे में कांग्रेस के मीडिया व कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली और अमेठी में कभी प्रत्याशी नहीं उतारा। राजनीतिक शिष्टाचार को निभाते हुए कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। उन्हींने यह भी कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराना है। भाजपा के खिलाफ करहल और जसवंतनगर सीटों पर लड़ाई कमजोर न हो, इसलिए भी पार्टी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने से परहेज किया है।

"क्रिप्टो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लगाया जाएगा।

चिदंबरम ने कहा कि, "यह स्पष्ट रूप से किसी को लाभान्वित करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की 99.9 प्रतिशत जनता के लिए डिजिटल असैट्स कोई मायने नहीं रखती।"

राहुल गांधी के "ज़ीरो-सम बजट" ट्वीट पर चिदंबरम ने ठेठ तमिल भाषा में टिप्पणी की।

उन्होंने इसे इस तरह से वर्णित किया- ज़ीरो कैश एसिस्टैन्स, जिन लोगों ने अपनी नौकरियां खोईं, उनके लिए ज़ीरो, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ज़ीरो, एम.एस.एम.ई. के लिए ज़ीरो, जो लोग कुपोषण और भुखमरी से त्रस्त हैं, उनके लिए ज़ीरो, अतः ज़ीरो प्लस ज़ीरो, प्लस ज़ीरो, प्लस ज़ीरो, प्लस ज़ीरो का योग भी ज़ीरो ही हो सकता है।

'या तो भारत के कानून का सम्मान करे अन्यथा अपनी दुकान बंद करे ट्विटर'

नई दिल्ली, 1 फरवरी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक सामग्री हटाने के अपने आदेश का सम्मान नहीं करने के लिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर करारा प्रहार किया। अदालत ने ट्विटर से यह बताने के लिए कहा है कि इस मुद्दे पर क्यों न उसे बंद कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा, आपको अनिवार्य रूप से देश के कानून का पालन करना होगा, नहीं तो आप अपनी दुकान बंद कर दें।

मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एम. सत्यनारायण मूर्ति की खंडपीठ ने कहा कि ट्विटर की गतिविधि अदालत की अवमानना की तरह है। खंडपीठ ने सोमवार को पूछा कि उसके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया क्यों न शुरू की जाए। कोर्ट ने ट्विटर को अगली सुनवाई के दिन इस

- **आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेशों की अवहेलना के मामले में ट्विटर के खिलाफ यह सख्त टिप्पणी की।**

संबंध में एक शपथपत्र दाखिल कराने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई सात फरवरी को तय कर दी। कड़ा रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट ने ट्विटर से कहा कि बचने के लिए वह तकनीकी का सहारा नहीं ले सकती।

हाई कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा, पिछली सुनवाई के दौरान हमने स्पष्ट आदेश दिया था कि आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाया जाए। ऐसा करने में विफल रहने पर अदालत की अवमानना मानी जाएगी। यदि आपको अपनी सेवा जारी रखनी है तो आपको अनिवार्य रूप से देश के कानून का पालन करना होगा, नहीं तो आप अपनी दुकान बंद कर दें।

विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर सत्ताधारी वाई.एस.आर. कांग्रेस के सदस्यों एवं समर्थकों द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक एवं अपमानजनक पोस्ट से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई चल रही है। इसी मामले की सुनवाई में सोमवार को ट्विटर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा। हाई कोर्ट के आदेश पर सी.बी.आई. इस मामले की जांच कर रही है और इस सिलसिले में अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

'करोना से बच्चों को भारी नुकसान हुआ अब उनके लिए बजट आवंटन में भी कटौती हुई'

कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि, मोदी सरकार ने बाल अधिकारों के मद में आवंटित राशि में 23 फीसदी की कटौती की है

नई दिल्ली 1 फ़रवरी (वार्ता)। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में बच्चों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के मद में कटौती करने पर चिंता जाहिर की है।

के.एस.सी.एफ. ने बयान जारी कर कहा कि पिछले बजट में बच्चों के मद में कुल बजट का 2.46 फीसदी धन आवंटित किया गया था , जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह घटकर 2.35 फीसदी रह गया है। यह 2008 से बाल अधिकारों के मद में आवंटित की जा रही अभी तक की सबसे कम धनराशि है।

- **पिछले बजट में बच्चों के मद में कुल बजट का 2.46 फीसदी धन आवंटित किया गया था , जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह घटकर 2.35 फीसदी रह गया है। यह 2008 से बाल अधिकारों के मद में आवंटित की जा रही अभी तक की सबसे कम धनराशि है।**

उन्होंने कहा कि करोना महामारी ने बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य से लेकर उनकी देखभाल, पोषण, पेयजल, स्वच्छता और संरक्षण को काफी प्रभावित किया है। समाज के हाशिए पर रहने वाले गरीब लोगों की आमदनी में कमी होने से उनके बच्चों को बाल श्रम, ट्रैफिकिंग, शोषण, यौन दुर्व्यवहार, अपमान और अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए केंद्रीय बजट में बच्चों के हित में धनराशि बढ़ाए जाने की जरूरत थी। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन महिला और बाल विकास मंत्रालय के बजट आवंटन पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पिछले वित्तीय साल के मुकाबले आठ प्रतिशत की कमी की गई है, जो वर्ष 2020-21 के 20,401 करोड़ रूपये से घटकर 2022-23 में 18,859 करोड़ रूपये हो गया है। पिछले चार वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण भी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) के कार्यान्वयन के लिए किए गए बजट आवंटन में लगातार कमी का संकेत देता है।

तेजपाल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एन.वी.रमना एवं न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना तथा हिमा कोहली की बैंच ने उस समय दिया, जब तेजपाल की ओर से प्रस्तुत हुये वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने इस केस को शीघ्र सूचीबद्ध किये जाने का अनुरोध किया, क्योंकि दो जज इसकी सुनवाई से अलग हो चुके हैं। सी.जे.आई. ने कहा, "हम इसे पुनः सूचीबद्ध करेंगे।" दो अलग-अलग सुनवाइयों में अलग हो जाने वाले दो जज हैं- न्यायमूर्ति यू.यू. ललित तथा एल. नागेश्वर राव। तेजपाल ने अपील में मांग की है कि, गोवा सरकार द्वारा की गई अपील की "इन -कैमरा" सुनवाई की जाये। ज्ञातव्य है कि 21 मई 2021 को ट्रायल कोर्ट उसे दोषमुक्त घोषित कर चुका है।

निर्मला सीतारमण इकॉनमी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहे थे कि, विन्टर ओलम्पिक्स में शामिल होने वाले सभी लोग इस मुद्रा से भुगतान करें, तथा सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थीं।

लेकिन ओमिक्रॉन फैलने तथा कोविड आइसोलेशन के नये तथा अत्यधिक सख्त नियमों के कारण, चीन के चीनी सी.बी.डी.सी. की लॉन्चिंग रोक दी है।

दूसरी तरफ, चीनी एन.एफ.टी. (नॉन फंजिबल टोकन्स) जैसी डिजिटल परिसम्पत्तियों का ट्रेड बढ़ रहा है। उदाहरण के लिये इससे डिजिटल आर्ट को खरीदा जा सकता है।

यह लोगों के पास है तथा डिजिटल असैट्स मार्केट में खरीदी-बेची जा रही है। भारतीय लोग भी ऐसी एन.एफ.टी. खरीद-बेच रहे हैं तथा अब इस प्रकार की करैन्सी की ट्रेडिंग पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

एन.एफ.टी. रियल टाइम डिजिटल आर्ट है। बहुत से आर्टिस्ट अपने आर्टवर्क को डिजिटल फॉर्मेट में बदल रहे हैं तथा इन्हें डिजिटल नीलामी प्लेटफॉर्मों पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इन डिजिटल आर्ट्स के मालिक अपने आर्टवर्क के स्वामित्व को बनाये रखते हैं तथा इन्हें खदीद-बेच सकते हैं।

वित्त मंत्री वर्तमान प्राइवेट डिजिटल करैंसियों तथा बड़ी ट्रेडिंग करने की प्रवृत्तियों में भारतीयों के प्रवेश को हतोत्साहित करने या कम करने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय खरीददार वर्तमान ग्लोबल प्राइवेट डिजिटल करैन्सियों को लेकर दिन पर दिन बहुत सक्रिय हो रहे थे। सुस्थापित डिजिटल करैंसी एक्सचैंजों में ट्रेडिंग की मात्रा बढ़ती जा रही है।

इनके लिये, जब तक सब सही चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि लोग बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग करके बढ़ते हुए दायित्वों (ऑब्लिगेशन) को कम कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में घाटे का मतलब भुगतान संबंधी ऑब्लिगेशन भी हो सकता है।

डिजिटल असैट्स ट्रेडिंग पर टैक्स लगाये जाने से, डिजिटल एक्सचेंज तथा डिजिटल करैंसी लेने वाले लोग-दोनों ही हतोत्साहित अनुभव करेंगे। इसलिये, ऐसा संभव है कि वर्तमान प्राइवेट डिजिटल करैंसियों की ट्रेडिंग तथा कुल भारतीय निवेश पर टैक्स लगने का प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

इसलिये, इस पर टैक्स लगने का नतीजा यह होगा कि, उन भारतीयों की संख्या में कमी आएगी जो वर्तमान डिजिटल असैट्स तथा करैंसियों की ओर जा रहे हैं।

दूसरी तरफ, भारत डिजिटल करैंसी के वैश्विक लेन-देन के मामले में सबसे आगे होगा। ज्ञातव्य है कि डिजिटल करैंसी मूलभूत रूप से करैंसी की परिकल्पना (कॉन्सेप्ट) को पूरी तरह बदल रहा है। कौड़ियों से आकारविहीन डिजिटल करैंसी तक की यात्रा अर्थव्यवस्था की प्राचीनतम संस्थाओं में एक धन की अवधारणा तक के विकास की कहानी है।

'बजट पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने वाला'

नई दिल्ली, 1 फरवरी (वार्ता)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आम बजट 2022-23 को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि इसमें गरीबों, कमजोरों, आदिवासियों, युवाओं, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है और यह पूरी तरह से

- **चिदंबरम ने कहा कि, लोककल्याण को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है और सभी क्षेत्रों में सब्सिडी पर कटौती की गई है।**

'पूंजीवादी बजट' है।

चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा कि, देश की अर्थव्यवस्था 2019-20 के स्तर पर है यानी दो साल पीछे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है लेकिन सरकार ने इससे उभरने के लिए कोई कदम बजट में नहीं उठाए हैं।

वित्त मंत्री ने "गैर राजनीतिक"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बोल्ड अप्रोच अपनातीं।

लेकिन इस अप्रोच में प्राइस लाइन बाधा होगी। चूंकि हाल ही के महीनों में महंगाई स्थिर होकर मजबूत हो चुकी है, इसलिए क्षमता निर्माण का भारी व्यय आर्थिक सिस्टम में और पैसा ला सकता है जिससे मंहगाई बढ़ेगी।

इसके साथ ही "प्राइस लाइन" पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि महंगाई के एक बार स्थिर हो जाने पर उसे रोकना मुश्किल होगा। और तेजी से बढ़ती महंगाई कुल मिलाकर खेल बिगाड़ सकती है।

बजट किसी उद्योग अथवा अर्थव्यवस्था के किसी भाग को प्रोत्साहित करने के लिए किन्हीं "इन्सैन्टिब्ज़ या छूटों में फेरबदल का प्रयास नहीं कर रहा है। यह उस बड़े लक्ष्य पर अपनी आस्था प्रकट कर रहा है जो सभी सैक्टर्स को सक्रियता के एक उच्च स्तर पर ले जाएगा।

सीतारमण ने कड़ी समग्र रणनीति के अलावा, बजट में अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन की तकनीकी का समावेश किया है। वित्त मंत्री ने कृषि विकास के लिए "ड्रोन्स" के उपयोग तथा क्षेत्रीय भाषाओं के बढ़े हुए "डिजिटल एजूकेशनल कन्टैन्ट्स" के जरिए स्थानीय तकनीकी, ई-एजूकेशन और शिक्षण की बात की है और इन सबसे अधिक उन्होंने अब एक अधिकारिक डिजिटल करैन्सी की घोषणा की है।

एक परम्परागत बजट की अपेक्षा एक अधिक अवधि के विकास पथ पर चलने के चक्कर में उनके पास करों पर गौर करने का समय नहीं रहा। उन्होंने टैक्स के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा है और सभी टैक्स रेट्स अपरिवर्तित रखी गई हैं।

वास्तव में इसने थोड़ा भ्रम पैदा कर दिया है क्योंकि टैक्सेशन के वकील और विशेषज्ञ इस पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि इनकम टैक्स या कस्टम अथवा ऐसे अन्य करों को क्या हो गया है।

वित्त मंत्री ने भारतीय घरेलू उद्योगों को ज्यादा संरक्षण प्रदान करने के लिए कस्टम ड्यूटीज़ में ही आंशिक फेरबदल किया है। संक्षेप में, वित्त मंत्री ने यह बजट बनाने में महाभारत से प्रेरणा प्राप्त की है तथा वे उद्धृत करती हैं:

"राजा को किसी भी तरह की विलासिता त्याग कर और राजधर्म अपनाकर अपनी जनता के योगक्षेम (कल्याण) के प्रबंध करने चाहिए और साथ ही धर्मानुसार टैक्स एकत्र करने चाहिए।" अन्ततः, उन्होंने पहली बार एक "धार्मिक" बजट पेश किया है।

'आरोप लग...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो और कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

पायलट ने कहा कि, लाखों परिवारों को यह सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है, ऐसे में सरकार को यह कदम उठाना ही होगा क्योंकि हम किसी नौजवानों को अकेला नहीं छोड़ सकते। जब लाखों का जीवन और भविष्य किसी मुद्दे से जुड़ा होता है, तो वह मुद्दा अपने आप ही गंभीर हो जाता है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600